(ख) इन परीक्षाओं को आयोजित करने वाले विश्वविद्यालयों के नाम क्या है; और

(ग) तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं द्वारा समाचार-पत्रों में बी० एड० तथा एल०एल०बी० की परीक्षाएं प्राइवेट रूप से पास करने के सम्बन्ध में जारी किए गए विज्ञापनों की सरकार को जानकारी है ।

(ख) और (ग). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दो-वर्षीय एल०एल०बी० (शैक्षिक) पाठ्यक्रम पत्राचार के माध्यम से शुरू करने का जम्मू विश्वविद्यालय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है । मदुरै तथा मैसूर विश्वविद्यालयों में बी०जी०एल० के लिए भी पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था है ।

बम्बई, जम्मू, मैसूर तथा राजस्थान विश्वविद्यालयों में बी०एड०डिग्री के पत्राचार पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है । जम्मू व काश्मीर में स्नातक डिग्री तथा कम से कम 7 वर्ष की सेवा रखने वाला शिक्षक बी०एड० के पत्राचार पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने का पात्र है । राजस्थान में यह अनुभव एक मान्यता-प्राप्त शैक्षिक संस्था में 3 वर्ष का है । बम्बई और राजस्थान के विश्वविद्यालयों में परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी की व्यवस्था है । कोई विश्वविद्यालय पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से एल०एल०एम० डिग्री के अध्ययन के लिए सुविधाएं प्रदान नहीं कर रहा है ।

चावल मिलों द्वारा धान का वसूली मूल्यों से भी कम मूल्यों पर खरीदा जाना

2577. **श्री मही लाल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल मिलें किसानों से धान सरकार द्वारा निर्धारित दरों से भी पांच से दस रुपये तक कम दरों पर खरीद कर रही है; और

(ख) किसानों को धान के निर्धारित मूल्य दिलाना सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रबंध करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना से पता चलता है कि चावल मिलों द्वारा किसानों से सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर धान की खरीदारी करने की कोई शिकायत नहीं है ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम, जहां कहीं वह वसूली एजेंसी के रूप में काम करता है, और राज्य सरकारों ने सरकार द्वारा धान की विभिन्न किस्मों के लिए निर्धारित समर्थन मूल्यों पर उत्पादकों द्वारा बिक्री के लिए लायी गई उचित औसत किस्म की धान की सारी मात्रा की खरीदारी करने के लिए क्रय केन्द्र खोल कर व्यापक प्रबन्ध किए हैं । कोई शिकायत प्राप्त होने पर, जहां कहीं और जब कभी मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से नीचे चले जाते हैं तब इन एजेंसियों द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्यों पर खरीदारी की जाती है ।

Utilization of Funds of Drought Prone Area Programme in Phulbani, Orissa

2578. SHRI SRIBATCHHA DIGAL: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the amount placed at the disposal of Drought Prone Area Pro-

gramme for utilisation in Phulbani District in Orissa State during the last three years;

(b) the amount utilised during the last three years; and

(c) in case, some amounts have been surrendered the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) An amount of Rs. 284.65 lakhs was placed at the disposal of Drought Prone Area Programme for utilisation in Phulbani District in Orissa State during the last three years.

(b) Rs. 213.49 lakhs was utilised during the last three years;

(c) An amount of Rs. 19,000 was surrendered due to non-appointment of staff.

Food for Works Programme in Orissa

2579. SHRI SRIBATCHHA DIGAL: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) why the Government are not taking up small projects like minor irrigation schemes, construction of roads, under Drought Prone Area Programme so as to provide food for work for the tribals in the backward districts of Orissa; and

(b) whether the Government propose to take such a policy decision; and if so, when?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) and (b). Construction of roads is not a programme component under Drought Prone Areas Programme. Minor irrigations schemes, however, are taken up under the programme. Approved outlay for minor irrigation in the selected districts of Kalahandi and Phulbani in Orissa is Rs. 480.16 lakhs during the Fifth Plan. Expenditure incurred on minor irrigation upto September 1978 is Rs. 311.92 lakhs. The Government of Orissa have been allotted 10,000 metric tonnes of wheat so far under the food for work programme.

Expenditure on Hosting the Theatre Artists from Moscow

2580. SHRI M. A. HANNAN ALHAJ: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether half of the total budget allocation for the current year of the Ministry has been spent on hosting the 'BOLSHOI' Theatre artists from Moscow who are currently in India;

(b) after such huge expenditure, whether the Ministry have taken care that the maximum number of Art lovers should be able to view the show; and

(c) the reasons why Ministry have arranged the show at Kamani Auditorium which has only 639 seats (out of which more than half are bound to go to the so-called V.I.Ps. and Government officials), and not at Vigyan Bhavan which has got a large auditorium and large stage to hold dance ensemble of the magnitude of Bolshoi Group?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) No, Sir.

(b) A large number of artists and leading figures in the field of dance and music were invited to the performances. On the inaugural day, 52 artists and specialists from the fields of dance and music, including 13 leading figures, attended. The special Bolshoi performance on the 27th was attended by 100 artists.